Daily Current Affairs

वर्ष 2023 में वैश्विक स्तर पर भारत में किया गया सर्वाधिक इंटरनेट शटडाउन

- एक्सेस नाउ और कीप इट ऑन गठबंधन की नई रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 2023 में दुनिया में सबसे अधिक इंटरनेट शटडाउन देखा गया,
- लगातार छठे वर्ष, भारत ने इंटरनेट शटडाउन में दुनिया का नेतृत्व किया।
- साथ ही अधिकारियों ने जानबूझकर हिंसा, युद्ध अपराध, लोकतंत्र पर हमले और अन्य अत्याचारों को छुपाने, सक्षम करने और बढ़ाने के लिए 39 देशों में कम से कम 283 बार इंटरनेट को बाधित किया, जिससे लाखों लोगों के मानवाधिकारों का हनन हुआ।
- 37 आदेशों के साथ, म्यांमार, जहां सेना ने 2021 में तख्तापलट में सत्ता पर कब्जा कर लिया, इंटरनेट शटडाउन की दूसरी सबसे बड़ी संख्या दर्ज की गई, इसके बाद ईरान (34), फिलिस्तीन (16), और यूक्रेन (8) हैं।

इंटरनेट शटडाउन क्या है?

- इंटरनेट या इलेक्ट्रॉनिक संचार में जानबूझकर किया गया व्यवधान जो उन्हें किसी विशेष आबादी के लिए या किसी स्थान के भीतर निष्क्रिय या व्यावहारिक रूप से अनुपयोगी बना देता है, इंटरनेट शटडाउन के रूप में जाना जाता है। यह आमतौर पर सूचना प्रवाह पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए किया जाता है।

Result mitra

रिपोर्ट से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बिंदुः

- रिकॉर्ड : भारत ने छठी बार, कम से कम 116 रिकॉर्ड शटडाउन के साथ दुनिया के इंटरनेट शटडाउन में सबसे आगे रहा;
- दायरा : पिछले पांच वर्षों में, भारतीय अधिकारियों ने 500 से अधिक बार किल स्विच मारा है, जिससे बार-बार दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में लाखों लोग अंधेरे में डूब गए हैं; [किल स्विच, जिसे औपचारिक रूप से आपातकालीन पावर ऑफ के रूप में भी जाना जाता है, एक सुरक्षा तंत्र है जिसका उपयोग आपातकालीन स्थिति में मशीनरी को बंद करने के लिए किया जाता है
- सबसे अधिक प्रभावित : मई और दिसंबर के बीच, मणिपुर में लगभग 3.2 मिलियन लोगों को 212 दिनों के राज्यव्यापी बंद का सामना करना पड़ा;
- अपराधी : कुल 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने 2023 में शटडाउन लगाया, जिनमें से सात ने पांच या अधिक बार इंटरनेट सेवाओं को बाधित किया;
- अवधिः पांच दिन या उससे अधिक समय तक चलने वाले शटडाउन 2022 में सभी शटडाउन के 15% से बढ़कर 2023 में 41% से अधिक हो गए
- डिजिटल विभाजन: 59% शटडाउन विशेष रूप से उस देश में मोबाइल नेटवर्क को लक्षित करते हैं जहां इंटरनेट एक्सेस वाले लगभग 96% लोग वायरलेस सेवाओं पर निर्भर हैं;

Resultmitra

- चुनौती: स्पष्ट आर्थिक प्रभावों, हाशिए पर मौजूद समूहों पर असंगत प्रभाव और अत्याचारों को बचाने के बावजूद, अधिकारी विरोध प्रदर्शनों, परीक्षाओं, चुनावों और सांप्रदायिक हिंसा के दौरान पूरे भारत में सभी स्तरों पर शटडाउन लागू करना जारी रखते हैं।

भारत में इंटरनेट शटडाउन के कानूनी प्रावधान

- दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144: यह जिला मजिस्ट्रेटों को खतरनाक स्थितियों के दौरान व्यापक शक्तियाँ देती है।
- आईटी (संशोधन) अधिनियम, 2008 की धारा 69 (ए) सरकार को विशेष वेबसाइटों को ब्लॉक करने की शक्ति देती है, न कि संपूर्ण इंटरनेट को।
- भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885: यह निर्धारित करता है कि केवल संघ या राज्य का गृह संचिव ही आदेश पारित कर सकता है, और इस आदेश में इंटरनेट सेवाओं के निलंबन के निर्णय के कारणों को शामिल करना होगा।
- "अपरिहार्य परिस्थितियों" में, आदेश केंद्र या राज्य के गृह सचिव द्वारा अधिकृत संयुक्त सचिव या उससे ऊपर के बैंक के अधिकारी द्वारा जारी किया जा सकता है।
- समीक्षा समितिः आदेश जारी होने के अगले दिन एक समीक्षा समिति को भेजा जाना चाहिए, और टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 5(2) के अनुपालन का आकलन करने के लिए समिति द्वारा पांच दिनों के भीतर इसकी समीक्षा की जानी चाहिए।
- यदि भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 5(2), दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन (सार्वजनिक आपातकाल और सार्वजनिक सुरक्षा) नियम, 2017 को एक साथ पढ़ें तो निष्कर्ष निकलता है कि सरकार के पास सार्वजनिक आपातकाल के दौरान या सार्वजनिक सुरक्षा के लिए संदेशों के प्रसारण को रोकने की शक्ति है।
- हालाँकि, आदेश "सार्वजनिक आपातकाल" के दौरान या "सार्वजनिक सुरक्षा के हित" में होना चाहिए। साथ ही, निलंबन "आवश्यक" और "अपरिहार्य" होना चाहिए।

Result mitra

अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ वाद, 2020:

- इस केस ने इंटरनेट शटडाउन को केवल उन असाधारण स्थितियों तक सीमित कर दिया जहां कोई सार्वजनिक आपातकाल या सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा हो।
- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि इंटरनेट के माध्यम से सूचना तक पहुंच भारतीय संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार है।
- सरकार द्वारा इंटरनेट एक्सेस पर कोई भी प्रतिबंध अस्थायी, सीमित दायरे वाला, वैध, आवश्यक और आनुपातिक होना चाहिए।
- इंटरनेट पहुंच को प्रतिबंधित करने वाले सरकार के आदेश न्यायालयों द्वारा समीक्षा के अधीन हैं।

Q. 'इंटरनेट शटडाउन' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 भारत में एकमात्र कानून है जो इंटरनेट सेवाओं के निलंबन से संबंधित है।

2. एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 2023 में दुनिया में सबसे अधिक इंटरनेट शटडाउन देखा गया, जो लगातार सातवाँ वर्ष से एक रिकॉर्ड है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही नहीं है/हैं?

A) केवल 1

B) केवल 2

C) 1 और 2 दोनों

D) उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर: C) 1 और 2 दोनों

Result mitra

स्पष्टीकरण :

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000, आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी), 1973 की धारा 144 और टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 तीन कानून हैं जो इंटरनेट सेवाओं के निलंबन से संबंधित हैं।

2017 में, केंद्र सरकार ने इंटरनेट के निलंबन को नियंत्रित करने के लिए टेलीग्राफ अधिनियम के तहत दूरसंचार सेवाओं (सार्वजनिक आपातकालीन या सार्वजनिक सेवा) के अस्थायी निलंबन नियमों को अधिसूचित किया। ये नियम भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 5(2) से अपनी शक्तियाँ प्राप्त करते हैं। वहीं एक्सेस नाउ और कीप इट ऑन गठबंधन की नई रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2023 में दुनिया में सबसे अधिक इंटरनेट शटडाउन देखा गया, जो लगातार छठा वर्ष एक रिकॉर्ड है। कीप इट ऑन गठबंधन के अनुसार पिछले साल देश में 116 बार इंटरनेट बंद किया गया था। अतः दोनों कथन सही नहीं है और विकल्प C इस प्रश्न का सही उत्तर है।

Result mitra